न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 34/2024

अनवान : –

1. गुंजन नाबालिग पुत्री रतनसिंह जरिये कुदरती बली माता राजेश कंवर पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. हर्ष वर्धन नाबालिग पुत्र रतनसिंह जरिये कुदरती बली माता राजेश कंवर पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मदनसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. रतनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय फेफाना/खुंईया/नोहर/रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायलान**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 603/507 की कुल 13.5800 हैक्ट भूमि में से 1509/13580 हिस्सा गैरसायल स0 1 के व 1509/13580 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 ता 2 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 ता 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है सायल संख्या 1 जो की विकलांग है तथा सायलान नाबालिग है। उक्त वाद भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज होने से गैरसायलान उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने [illegible] किया गया। रोही मौ[illegible] बारानी तहसील नोहर के खाता स0 603/507 की कुल 13.5800 [illegible]क्ट भूमि में गैरसायल [illegible] 1 व 2 प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम 1509/13580 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब इस आशय का पेश किया की वाद भूमि पैतृक भूमि नही है सायलान का वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही है न्यायालय हाजा में सन्दीप सिंह बनाम मदनसिंह प्रकरण स0 12/2019 निर्णय दिनांक 01.07.2019 के अनुसार मदनसिंह के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में सायलान व गैरसायल स0 1 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये है। उक्त डिक्री के रहते सायलान वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है। तत्कालिन वाद में गैरसायल स0 4 ने अपना हक हिस्सा गैरसायल स0 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार चार पिढी तक पैतृक भूमि साबित करना होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों बिरजूसिंह के नाम दर्ज रही है और उनके के बाद सायल के दादा व पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 व 2 [illegible] कार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्म[illegible] हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 603/507 की कुल 13.5800 हैक्ट भूमि में गैरसायल संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1509/13580 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:10 IST
Reason: SelfAttested